

THE ECONOMIC TIMES नई दिल्ली गुरुवार 2 अगस्त 2018

## रेपो रेट में इजाफे से मकानों की बिक्री को लगेगा झटका

[ ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली ]

दो महीने में दूसरी बार रेपो रेट बढ़ने से ट्रेड-इंडस्ट्री खासकर रियल एस्टेट के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। बिल्डरों का कहना है कि इससे मकानों की बिक्री को झटका लगेगा और बैंकों ने रेट बढ़ाने में तेजी दिखाई तो महीनों की सुस्ती से उबरने की रफ्तार फिर थम सकती है। उद्योग चैंबर्स ने सरकार को चेताया है कि वह औद्योगिक ग्रोथ को मुट्ठी में मानकर न चले और अब दरों में स्थिरता लाने पर जोर दे। नेशनल रियल एस्टेट डिवेलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी ने कहा, 'इस कदम से बायर्स सेंटीमेंट पर नकारात्मक असर पड़ेगा और मकानों की बिक्री में गिरावट आएगी।'

क्रेडाई के वाइस प्रेसिडेंट मनोज गौड़ ने कहा कि सुस्ती के दौर से गुजर रहे सेक्टर में जान फूंकने के लिए बेहतर होता कि आरबीआई ने रेट घटाए होते। यह सेक्टर बैंक लोन पर सबसे ज्यादा निर्भर है और रेट घटने से डिमांड में तेजी आती। आगामी फेस्टिव सीजन के मद्देनजर सेल्स को स्कीमों और ऑफर्स से लबरेज करने में जुटे रियल्टर्स को आशंका है कि बैंकों ने भले ही पिछली कटौतियों को पासऑन करने में कोताही बरती हो, लेकिन दो बार की बढ़ोतरी को वे तुरंत लागू करेंगे।

क्रेडाई गाजियाबाद के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता ने कहा कि लेंडिंग रेट में इजाफे का सीधा असर इस सेक्टर की

ग्रोथ पर पड़ता है। रेट बढ़ने से बिल्डर और ग्राहक दोनों की कॉस्ट बढ़ेगी और डिमांड में कमी आएगी। महंगाई की वजह से यह आरबीआई की मजबूरी हो सकती है, लेकिन लगातार दो बढ़ोतरी से इंडस्ट्री सेंटीमेंट को झटका लगेगा।

प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया के सीएमडी शिशिर वैजल ने इसे महंगाई के रुझान के मद्देनजर उम्मीद के मुताबिक बताया। सीबीआई के इंडिया चेयरमैन अंशुमान मैगजीन ने कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद ज्यादातर बैंक अपने डिपॉजिट और लोन रेट को नए सिरे से तय करेंगे। महागुन ग्रुप के डायरेक्टर धीरज जैन ने कहा कि एक बढ़ोतरी के बाद आरबीआई एक कटौती कर संतुलन कायम कर सकता था, जिससे सेक्टर का हौसला बना रहता। हालांकि अब भी बैंकों के पास गुंजाइश है कि वे अगर कटौती नहीं तो कम से कम रेट स्थिर रख सकते हैं।

उधर, उद्योग संगठनों ने अब आगे बढ़ोतरी के प्रति चेताया है। एसोचैम के प्रेसिडेंट संदीप जजोदिया ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेट्री को औद्योगिक रिकवरी को ग्रैंटेड मानकर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब भी उद्योग जगत का बड़ा हिस्सा कर्ज में डूबा है। फिक्की के प्रेसिडेंट रमेश शाह ने उम्मीद जताई कि लगातार दूसरी कटौती के बाद रेट में आगे स्थिरता आएगी। उन्होंने सरकार से महंगाई थामने के दूसरे उपायों पर भी काम करने को कहा।

क्रेडाई के वाइस प्रेसिडेंट मनोज गौड़ ने कहा कि सुस्ती के दौर से गुजर रहे सेक्टर में जान फूंकने के लिए बेहतर होता कि आरबीआई ने रेट घटाए होते। यह सेक्टर बैंक लोन पर सबसे ज्यादा निर्भर है और रेट घटने से डिमांड में तेजी आती। आगामी फेस्टिव सीजन के मद्देनजर सेल्स को स्कीमों और ऑफर्स से लबरेज करने में जुटे रियल्टर्स को आशंका है कि बैंकों ने भले ही पिछली कटौतियों को पासऑन करने में कोताही बरती हो, लेकिन दो बार की बढ़ोतरी को वे तुरंत लागू करेंगे।